

3



अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म.प.  
II निगरानी दमोह/भू.रा/2018/1531  
गंगाराम कुमी मृत द्वारा वारसान गर्ण-

BOR

13 FEB 2018

1. प्रेमरानी कुमी उम्र 70 वर्ष बेवह गंगाराम कुमी
  2. श्यामलाल कुमी उम्र 42 वर्ष बल्ह स्व० गंगाराम कुमी
- दोनो निवासी ग्राम सतपारा तह० पथरिया जिला दमोह म.प.  
.. निगरानीकर्तागण

II क्रिद्व।।

श्री गंगाराम कुमी  
द्वारा प्रस्तुत.  
अधिवक्ता  
कार्यालय कानून, सागर तस्माग,  
सागर (म.प.)  
13 FEB 2018

1. कैदारनाथ तनयदामोदर पुसाद चौरहा  
निवासी ग्राम सतपारा तह० पथरिया जिला दमोह म.प.
  2. म.प. शासन  
द्वारा कलेक्टर महोदय दमोह म.प.
- ... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प. भू. रा. संहिता

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी मान्य अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 220/अ-5 वर्ष 2012-13 में पारित अपील निरस्ती आदेश दि० 02.11.2017 से परिदेवित होकर नकल प्राप्त में लगे समय को छोड़कर समयावधि के भीतर मूल अपीलार्थी गंगाराम कुमी की मृत्यु हो जाने से वारसान हक के आधार पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश की है :-

22/02/18


प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पति/पिता गंगाराम के नाम से मौजा सतपारा प.ह.नं. 4 तह० पथरिया जिला दमोह में खेतरा नंबर 1895/1 रकबा 1.58 हे० भूमि स्थित है, गंगाराम की मृत्यु भूमि में से 0.15 हे० भूमि कैदारनाथ चौरहा द्वारा प्रस्तुत रकबा 1/3 सम्बंधित तहसीलदार महोदय पथरिया के रा.प.क्र. 553/5 सूची में पारित आदेश दि० 18.08.2009 से पनरीक्षणकर्ता को किये

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1531

जिला - दमोह

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.03.2018	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलंब से पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन के विलंब का कोई स्पष्ट कारण न दिए जाने के कारण अपील निरस्त की है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में करते हुए अपील निरस्त की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>